सीआइटीयू कार्य समिति द्वारा घोषित आंदोलन का कार्यक्रम

सीआइटीयू कार्य समिति की 6–8 अक्टूबर को नयी दिल्ली में आयोजित बैठक ने व्यापक विचार विमर्श के बाद अभियान, आंदोलन और संघर्ष के अधोलिखित कार्यक्रम चलाने का फैसला किया:

1. निम्नलिखित मुद्दों पर आगामी 22 से 29 अक्टूबर तक देश भर में सप्ताहव्यापी अभियान चलाया जाएगा जो प्रदर्शनों ओर रैलियों में अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा:

- भारत–अमरीकी नाभिकीय समझौते के कार्यान्वयन के खिलाफ;
- महंगाई के खिलाफ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की मांग करते हुए;
- खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दिए जाने के खिलाफ और उसके कार्पोरेटीकरण के खिलाफ;
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून की मांग करते हुए और
- विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून तथा नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए।

2. आगामी 31 अक्टूबर को प्रदर्शनों, धरनों और रैलियों के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून के जरिए अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाएगा।

3. आगामी 20 नवम्बर को नयी दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक होगी।

4. गत 31 अगस्त को आयोजित मजदूर–किसान संयुक्त कन्वेंशन के निर्णयों को लागू किया जाएगा।

5. सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने की मांग करते हुए आगामी 22 अक्टूबर को तमाम यूनियनों द्वारा प्रधान मंत्री को टेलीग्राम भेजे जाएंगे।

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के कार्यक्रम

0 आगामी अक्टूबर–नवम्बर के दौरान संयुक्त राज्य स्तरीय कन्वेंशनों का आयोजन किया जाएगा।

0 आगामी 4 तथा 5 दिसम्बर को देशव्यापी जन–सत्याग्रह आयोजित किए जाएंगे।

0 19 नवम्बर को ठेका मजदूरों की अखिल भारतीय कन्वेंशन होगी।

सीपीएसटीसू के कार्यक्रम

0 आने वाले वेतन समझौतों के दृष्टिगत आगामी 7 नवम्बर को प्रदर्शनों, धरनों और रैलियों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के नियमित तथा ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाएगा।

0 सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनें आयोजन समिति के कार्यक्रमों में शामिल होंगी।

सीआइटीयू कार्य समिति ने मजदूर वर्ग को आह्वान किया है कि उपरोक्त कार्यक्रमों को सफल बनाएं और सरकार की जन विरोधी नीतियों को रुकवाने के लिए जबरदस्त देशव्यापी हड़ताल की तैयारी करें।

भीतर के पृष्ठों पर

	पृष्ठ
1. सीआइटीयू कार्य समिति का आह्वान ☐ तपन सेन	4
2. श्रमिक आंदोलन और वर्तमान दौर की चुनौतियां ☐ मोहम्मद अमीन	7
3. अक्टूबर क्रांति और सोवियत संघ का श्रमिक वर्ग ☐ एम के पन्धे	10
4. ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल का सम्मेलन ☐ स्वदेश देव राय	13
5. कामकाजी महिलाओं का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ☐ के हेमलता	15
6. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हड़ताल और उसके प्रभाव ☐ श्यामल चक्रवर्ती	17
7. महान क्रांतिकारी चे गुवेरा ☐ अर्धेन्दु दाक्षी	19
6. श्रमिक जगत की घटनाएं	23
7. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	26

यूपीए सरकार की जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाओ–सीआइटीयू कार्य समिति ने किया आह्वान

□ तपन सेन

यूपीए सरकार की जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन और अभियान चलाने के आह्वान के साथ सीआइटीयू कार्य समिति की 6 से 8 अक्टूबर, 2007 तक चली बैठक सम्पन्न हो गई। यह देशव्यापी आंदोलन और अभियान आगे चल कर देशव्यापी हड़ताल के रूप में अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा। कार्य समिति की बैठक में 109 सदस्यों ने भाग लिया जो सभी राज्यों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे द्वारा झण्डा फहराए जाने के साथ 6 अक्टूबर को बैठक शुरू हुई। यह बैठक नयी दिल्ली स्थित बी टी रणदिवे भवन के ऑडिटोरियम में हुई।

अध्यक्षीय भाषण

अपने अध्यक्षीय भाषण में सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के घटना विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसकी खास बात यह है कि विश्व के राजनीतिक–आर्थिक परिदृश्य में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपनी आक्रमक तथा प्रभुत्वकारी तिकड़में जारी रखने के बावजूद अमरीका और उसकी नीतियों का अलगाव बढ़ता चला जा रहा है। इराक में अमरीकी नीति को करारी मात मिली है। यहां तक कि इराक की मौजूदा कठपुतली सरकार को भी इराक से अमरीकी सेनाओं की वापसी की मांग उठानी पड़ रही है।

उनका कहना था कि अमरीका की प्रभुत्वकारी साजिशों की हर केन्द्र में निंदा हो रही है और जहां कहीं भी अमरीका ने हस्तक्षेप किया है फिर चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन हो, उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। लातीनी अमरीका के अंदरूनी मामलों में अमरीका के हस्तक्षेप को लेकर वहां उसे सबसे ज्यादा और जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा है।

दूसरी ओर उनका कहना था कि आइएमएफ और विश्व बैंक निदेशित आर्थिक निजाम की पोल दुनिया भर में खुल रही है और आर्थिक उदारीकरण का विरोध ज्यादा से ज्यादा तेज होता जा रहा है। विकसित और विकासशील दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्थाओं में हड़तालों तथा प्रदर्शनों की अनेकानेक कार्रवाईयां हुई हैं।

पंधे का कहना था कि कुल मिला कर आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में आक्रमकतावादी नीतियों, जो बुनियादी तौर पर साम्राज्यवाद द्वारा चलाई जा रही हैं, का विरोध ज्यादा से ज्यादा तेज होता चला जा रहा है।

उनका कहना था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व परिदृश्य में घटनाओं के इस निर्णायक मोड़ पर भारतीय शासकों ने साम्राज्यवादी शक्तियों से जुड़ने और अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ कायम करने के लिए गुटनिरपेक्षता के अपने रुख से भटकना शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि मजदूर वर्ग के आंदोलन को इन घटनाओं को उतने खतरे की आशंका के साथ नोट करना चाहिए जितनी खतरनाक यह हैं।

महासचिव की रिपोर्ट

कामरेड मोहम्मद अमीन ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्थिति के घटना विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था।

रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि विदेश नीति के मुद्दों के सिलसिले में शासक पार्टी की राजनीति में भारी दक्षिणपंथी झुकाव आया है, उसके आंतरिक मामलों में भी गम्भीर निहितार्थ होंगे। अमरीका तथा उसके सहयोगियों के साथ रणनीतिक सैन्य सहयोग तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास करना और केवल अमरीकी प्रशासन को खुश करने के लिए आइईए में दो बार ईरान के खिलाफ मतदान करना गुट निरपेक्ष देशों द्वारा अपनाए गए साझा रुख के खिलाफ है और साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यूपीए सरकार द्वारा किए गए वादे के खिलाफ है, जो सरकार की नीतियों में आए दक्षिणपंथी झुकाव के स्पष्ट संकेत हैं।

रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत–अमरीका नाभिकीय समझौते पर विवाद और वामपंथी पार्टियों और यहां तक कि नाभिकीय वैज्ञानिकों के एक बड़े तबके के कड़े विरोध और इस पर अमल न करने की मांग के बावजूद यूपीए सरकार के समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर देना इस बात का साफ संकेत है कि शासक वर्ग भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अमरीकी योजनाओं के अधीन कर रहे हैं।

महासचिव की रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया था कि हाइड कानून के संदर्भ में नाभिकीय समझौता अपने मौजूदा रूप में भारत को अमरीकी ब्लैकमेल का आसान शिकार बना देगा।, न केवल नाभिकीय परियोजनाओं के मामले में बल्कि अमरीकी साम्राज्यवादी प्रभुत्ववादी साजिशों के व्यापक क्षेत्र में भी। इस तरह के साम्राज्यवादी जाल में फंसने के हमारी आर्थिक आजादी तथा राजनीतिक सम्प्रभुता के लिए गम्भीर परिणाम होंगे और मजदूर वर्ग का आंदोलन अपनी ही कीमत पर इसकी अनदेखी कर सकता है।

जन विरोधी नीतियां

मोहम्मद अमीन ने सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों की भी कड़ी आलोचना की जिनके चलते अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं; बेरोजगारी तथा गरीबी बढ़ रही है और सकल घरेलू उत्पाद की दर बढ़ने के बावजूद किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इससे वितरण प्रक्रिया के पूरी तरह बैठ जाने का पता चलता है, जिसके चलते मुट्ठी भर अमीर वर्ग ने सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ती दर के सारे लाभ हड़प लिए हैं।

उनका कहना था कि शहरों और गावों दोनों ही जगह मेहनतकश अवाम, जो वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद की दर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है, को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। राज्य प्रायोजित श्रम कानूनों के उल्लंघन, सामाजिक सुरक्षा लाभों को खत्म करने और बड़े पैमाने पर ठेकाकरण के जरिए मजदूर वर्ग पर भारी हमला किया जा रह है।

उनका कहना था कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर देश की कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वे 65 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान करते हैं, किन्तु वही सबसे बदतरीन शिकार हैं। उसे एक सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून से वंचित किया जा रहा है। यह साझा न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लंघन है। संसद में पेश किया गया असंगठित क्षेत्र मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून पर्दापोशी के अलावा कुछ नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिससे सम्पूर्ण श्रम शक्ति के लिए समयबद्ध सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित होता हो।

उनका कहना था कि निजीकरण जारी है ओर निवेश फण्ड के नाम पर विनिवेश की मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। अंधाधुंध ढंग से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। खुदरा व्यापार का कारपोरेटीकरण किया जा रहा है और खुदरा व्यापार क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पिछले दरवाजे से घुसने की अनुमति दी जा रही है, जिससे छोटे दुकानदारों और इससे जुड़ी श्रम शक्ति के रोजगार तथा रोजी–रोटी के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह साम्राज्यवाद द्वारा चलाई जा रही नव–उदारवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विनाशकारी परिणाम हैं; वामपंथी दलों तथा श्रमिक आंदोलन के निरंतर विरोध के बावजूद यूपीए सरकार जिनका बड़े जोशो खरोश से पालन कर रही है।

महासचिव की रिपोर्ट में संतोष के साथ यह भी उल्लेख किया गया था कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा की पूरी तरह अवसरवादी भूमिका और उसकी साम्प्रदायिक साजिशों के विपरीत सरकार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मेहनतकश अवाम का देशव्यापी संघर्ष उभर रहा है। गत 10 जुलाई को आंगनवाड़ी मजदूरों द्वारा की गई जबरदस्त देशव्यापी हड़ताल; 8 अगस्त को हुई असंगठित मजदूरों की हड़ताल; आगामी 30 अक्टूबर को होने जा रही सरकारी कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल इत्यादि इस बात के संकेत हैं कि मेहनतकश अवाम सरकार की जन विरोधी साम्राज्यवाद परस्त तथा अमीर परस्त नीतियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट में जोर देकर यह कहा गया था कि भारत–अमरीका नाभिकीय समझौता विवाद के चलते जो राजनीतिक अस्थिरता बनती दिखाई दे रही है, उसके दृष्टिगत मजदूर वर्ग के आंदोलन को अपने आप को राजनीतिक संघर्ष करने की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ हमारा सम्पूर्ण संघर्ष और ज्यादा साम्राज्यवाद विरोध पर केन्द्रित होना चाहिए। इस सिलसिले में हमें अपनी कमजोरियों से उबरना होगा और उन संघर्षो को साम्राज्यवाद विरोधी अभियान के साथ जोड़ना चाहिए जो मजदूर वग्र के साथ वामपंथ और प्रगतिशील शक्तियों द्वारा देश भर में छेड़े जा चुके हैं।

रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मजदूर वर्ग को वामपंथ और प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिल कर शासक वर्ग द्वारा छेड़े गए कुत्सापूर्ण हमले का डट कर मुकाबला करना होगा। आगामी राजनीतिक संघर्ष में साम्राज्यवादी एजेंसियों की मदद से शासक वर्ग इससे भी ज्यादा आक्रमक रूप में सामने आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हमें भाजपा की साम्राज्यवाद परस्त तथा भूमण्डलीयकरण समर्थक नीतियों और उसके साम्प्रदायिक एजेंडे को भी बेनकाब करना चाहिए क्योंकि वह एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जनता में व्याप्त

असंतोष का इस्तेमाल करना चाहती है।

रिपोर्ट पर बहस और प्रस्ताव

रिपोर्ट पर हुई बहस में 42 सदस्यों ने भाग लिया और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे रिपोर्ट में सूत्रबद्ध की गई समझ और समृद्ध हुई। बहरहाल, विचार–विमर्श में चुनौतियों का मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। फिर चाहे ये चुनौतियां कितनी ही मुशकिल क्यों न हों।

कार्य समिति ने सर्वसम्मति से तीन प्रस्ताव पारित किए; पहला प्रस्ताव था भारत–अमरीका नाभिकीय समझौते के खिलाफ, जिसे श्यामल चक्रवर्ती ने पेश किया ओर ए सौंदर राजन ने इसका अनुमोदन किया। दूसरा प्रस्ताव था महंगाई के खिलाफ जिसे के हेमलता ने पेश किया तथा कश्मीर सिंह ठाकुर ने जिसका अनुमोदन किया। तीसरा प्रस्ताव था सेतु समुद्रम परियोजना को फौरन लागू करने की मांग करने हुए जिसे वासुदेव आचार्य ने पेश किया और जे हेमचन्द्रन ने जिसका अनुमोदन किया।

सीआइटीयू कार्य समिति ने गहरे दु:ख और शोक के साथ यह भी नोट किया कि गत 5 अक्टूबर को दोपहर बाद हरियाणा के पानीपत में एक टैक्सटाइल फैक्टरी में आग लगने से 10 मजदूरों की मौत हो गई।

इस हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्रशासन की पूरी मिलीभगत के साथ मालिक लोग कामकाजी स्थलों में वैधानिक सुरक्षा जरूरतों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इन गरीब मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सीआइटीयू ने मृतकों के परिजनों और घायलों को समुचित मुआवजा दिए जाने और दोषी मालिकों तथा राज्य प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किए जाने की मांग की।

उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा–'आप लोग मनमानी नहीं कर सकते'

"आप लोग मनमानी नहीं कर सकते और कर्मचारियों को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना न आखरी फैसला कर सकते हैं और न ही उनकी सेवा शर्तों में मन चाहा बदलाव ला सकते हैं" ये शब्द उच्चतम न्यायालय के हैं जो उसने 11 अक्टूबर को बालको कैपटिव पावर पलांट (बीसीपीपी) मजदूर संघ तथा अन्यों की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध याचिका दायर करने की अनुमति देते समय कहे थे।

नेशनल थर्मल पावर कापोरेशन (एनटीपीसी) की ओर से काम पर रखे गए 200 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं भारत एल्युमीनियम कम्पनी (बालको) जो बुनियादी तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम था और सरकार की विनिवेश की नीति के चलते बालको स्टरलाइट के पास चला गया था, में तबदील कर दिए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए दाखिल करते समय शीर्ष न्यायालय ने इस तरह के फैसले को मनमाना माना जाएगा क्योंकि यह संविधान की धारा 14 जो कर्मचारी को कानून के सामने समानता का अधिकार देती है, का उल्लंघन है।

जस्टिस तरुण चटर्जी और जस्टिस पी स्थासिवन पर आधारित एक खण्ड पीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी कर्मचारी की मर्जी के बिना उसकी सेवा को एक सेवा योजक से दूसरे सेवा योजक के पास तबदील नहीं किया जा सकता। अपनी सेवाओं को निजी क्षेत्र के एक उपक्रम में तबदील कर दिए जाने से दु:खी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया किन्तु उसने इसमें दखल देने से इन्कार कर दिया।

जस्टिस पी स्थासिवन ने अपने फैसले में कहा "क्योंकि एनटीपीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है ओर अपने संविधानक जिम्मेदारी के चलते राज्य का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। विशेष तौर पर उन पदों के मामले में जिनके लिए 1986 और 1988 के बीच विज्ञापन दिए गए थे और जो उस समय बालको में नहीं थे। इन परिस्थितियों में एनटीपीसी की ओर से नियुक्ति पत्रों में दर्ज अनुच्छेद का बेजा इस्तेमाल करके चुने हुए कर्मचारियों की सहमति लेने का कोई औचित्य नहीं है।

खण्ड पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनटीपीसी ने अपनी सेवा शर्ते थोपने के लिए चुने हुए कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डाला है। यदि किसी कर्मचारी की सेवाएं एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में तबदील की जाती हैं तो उसके लिए त्रिपक्षीय समझौता होना जरूरी है जिसमें कर्मचारियों के अलावा दोनों उपक्रमों के प्रबंधन शामिल हों। यदि त्रिपक्षीय समझौता नहीं होता है तो कर्मचारियों की सेवाओं का तबादला किसी भी हालत में नहीं हो सकता। खण्ड पीठ ने कहा कि कर्मचारियों की सेवाएं एनटीपीसी से बालको में तबदील करना एक बुरी कार्रवाई है।

(साभार : 'द हिन्दु' दिनांक 12–10–2007)

श्रमिक आंदोलन और वर्तमान दौर की चुनौतियां

□ मोहम्मद अमीन

(सीआइटीयू कार्य समिति की नयी दिल्ली में 6–8 अक्टूबर, 2007 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट के प्रमुख अंश)

विदेश नीति के मामले में यूपीए सरकार की नीति अधिकाधिक दक्षिणपंथी होती चली जा रही है जिसका न केवल विदेश नीति पर अपितु देश के अंदरूनी मामलों पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की ओर से अपनाए गए संयुक्त रुख से हट कर अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों के साथ सामरिक सहयोग और संयुक्त सैनिक अभ्यास करना; अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अथवा आइएईए में दो बार ईरान के खिलाफ वोट देना इत्यादि अमरीकी प्रशासन को खुश करने के लिए की जा रही कार्रवाईयां इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि विदेश नीति में इस तरह का दक्षिणपंथी बदलाव आ रहा है जो यूपीए सरकार के उस आश्वासन का उल्लंघन है जो उसने संयुक्त राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम को तैयार करते समय दिया था। भारत–अमरीका परमाणु समझौते के विवाद को ही लीजिए यूपीए सरकार वाम पक्षी दलों द्वारा घोर विरोध किए जाने के बावजूद उसे लागू करने के लिए हठ कर रही है। यहां तक कि परमाणु वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग भी उसका विरोध कर रहा है और उसे लागू न करने की मांग कर रहा है। इससे क्या संकेत मिलता है? यही कि सत्ताधारी वर्ग भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दरकिनार करके अमरीकी साम्राज्यवाद का दुमछल्ला बनने के लिए बेताब है। वह अमरीकी साम्राज्यवाद की खेल के मकड़ जाल में उलझता चला जा रहा है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में अमरीकी दबाव को झेलने की ताकत नहीं है। उसे खुश करने के चक्कर में वह गुट निरपेक्षता की नीति का बलिदान कर रही है जिसका विकास करने में पूरे छः दशक लगे हैं। वह किसी भी कीमत पर अमरीकी साम्राज्यवाद को खुश रखना चाहती है। इससे यही जाहिर होता है कि अमरीकी प्रशसन का शिकंजा कसता चला जा रहा है और भारत के शासक वे चाहे यूपीए मार्का के हों या एनडीए मार्का के उससे बच कर निकल नहीं सकते। वास्तव में, देश की वाम पक्षी एवं प्रगतिशील ताकतों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है; देश के श्रमिक आंदोलन के सामने प्रमुख कार्य इसी चुनौती का सामना करने का है क्योंकि देश की आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था और सम्प्रभुता के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है।

भारत–अमरीका परमाणु सौदा

इस संदर्भ में भारत–अमरीका परमाणु सौदे की असलियत को बेनकाब किए जाने की जबरदस्त जरूरत है। सत्ताधारी श्रेणियां प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वाम पक्षी एवं प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ निंदा अभियान चलाया जा रहा है। उनका ऐसा करना स्वाभाविक है क्योंकि भारत का सत्ताधारी वर्ग अपने संकीर्ण लाभों के लिए जिनके बारे में अधिकतर उसे भ्रांतियां ही हैं, अमरीकी साम्राज्यवाद का कनिष्ठ सहयोगी बनने के लिए बेताब हैं। भारत–अमरीका परमाणु सौदा देश के हितों के खिलाफ है और यह सौदा भारत की सम्प्रभुता को दांव पर लगा कर किया गया है, इन सब आरोपों का जवाब सत्ताधारी नहीं दे पा रहे हैं। वे इस बात को भी समझने में नाकाम रहे हैं कि अमरीका इस उपमहाद्वीप पर अपनी दादागिरी थोंपना चाहता है और यही बात उसकी पूरी खेल की केन्द्रीय धुरी है।

भारत सरकार और अमरीका के बीच परमाणु सहयोग पर सम्पन्न 123 समझौता उस व्यापक गठजोड़ का केवल एक हिस्सा ही है जो यूपीए सरकार ने अमरीका के साथ किया है। ठोस शब्दों में कहें तो यह समझौता उसी गठजोड़ का एक अभिन्न अंग है; यह सम्पूर्ण नव–उदारवादी राजनीतिक–आर्थिक नीति को आगे बढ़ाने की कार्रवाई मात्र नहीं है। इस नीति के निर्धारण के पीछे अमरीकी साम्राज्यादियों का दिमाग काम कर रहा है और उनके इस खेल में भारतीय शासक उसे खुश करने की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। भारत के प्रधान मंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति की ओर से वाशिंगटन में जुलाई 2005 को जो सांझा बयान जारी किया गया था, उसमें यह बात वाजह कर दी गई थी। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तथा परमाणु सहयोग इस समझौते के अन्तर्गत आ जाता है। इन दोनों के गठजोड़ में केवल परमाणु सहयोग ही शामिल नहीं है बल्कि तथाकथित लोकतंत्र को बढ़ावा देने और भारत की अर्थव्यवस्था को अमरीका के हितों के अनुकूल तथा उसके साथ सामरिक सैन्य सहभागिता के लिए नए सिरे से ढालने की बातें भी इसमें की गई हैं।

भारत में अमरीका के राजदूत डेविड मलफोर्ड ने 24 अप्रैल, 2006 को वाशिंगटन डीसी में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते समय इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया था कि भारत–अमरीका द्विपक्षीय परमाणु समझौतों और आपसी समझ के द्वारा किस तरह अमरीका के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा गया है। डेविड मलफोर्ड के शब्दों में "भारत में 1990 के दशक में बुनियादी तबदीलियों का दौर शुरू हो गया था।" ...पहले जो सुधार किए गए वे सही थे और उन सुधारों का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था के किवाड़ पूरी दुनिया के लिए खोलना था और अपनी अर्थव्यवस्था

को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना था। यह सब हो रहा है और इस प्रक्रिया में वे अपनी गुट निरपेक्षता की नीति रूपांतरण भी कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि अब उन्हें अमरीका के साथ निकट सम्बन्ध बनाए रखने की जरूरत है। ... और यह (परमाणु) समझौता कहने को भले ही एक पक्षीय नहीं हो पर इस दृष्टि से यह एक पक्षीय ही है क्योंकि भारत को अपनी जकड़ में रखने के लिए अमरीका में एक कानून है। यही कानून इस समझौते का आधार बनेगा।" भारत का इस तरह साम्राज्यवाद के जाल में फंस जाने के भयंकर दुष्परिणाम निकलेंगे और श्रमिक वर्ग किसी भी स्थिति में इसकी अनदेखी नहीं कर सकता।

श्रमिक आंदोलन मूक दर्शक बन कर इस पूरे घटना क्रम को देख नहीं सकता। उसे इसके खिलाफ अपने अभियान में तेजी लानी होगी और देश की सम्प्रभुता तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इस परमाणु सौदे के पीछे की असलियत को जग जाहिर करना होगा; उसे यूपीए सरकार की इन राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिक वर्ग के बीच एक शक्तिशाली प्रतिरोध का निर्माण करना होगा। वाम पक्षी दलों और संसद सदस्यों की बहुसंख्या के विरोध के बावजूद यूपीए सरकार के परमाणु सौदे को अमल में लाने की हठ पर कायम रहने के कारण पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में हमारे लिए यह एक बेहद जरूरी काम बन गया है।

भाजपा की भूमिका

यहां उल्लेख किया जाना जरूरी है कि लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण अडवानी ने पहले–पहले परमाणु सौदे का विरोध किया था किन्तु अब उन्होंने उसके ठीक विपरीत रुख अपना हुआ है; उनका यह किरदार उनकी घोर अवसरवादिता को नंगा करने वाला है। वास्तव में, भाजपा की ओर से किया गया परमाणु सौदे का तथाकथित विरोध उसकी साम्राज्यवाद विरोधी मानसिकता की उपज नहीं था बल्कि यह उसकी अवसरवादी राजनीति से प्रेरित था।

भाजपा अपने छः वर्षीय शासन काल में साम्राज्यवादियों के साथ अंदरूनी सांठ गांठ के लिए काफी बदनाम रही है। जसवंत सिंह–स्ट्रोबे तालबोट के बीच की गुप्त वार्ताएं, एल के अडवानी द्वारा सीआइए मुख्यालय का दौरा करना और अमरीका का स्वाभाविक सहयोगी बनने के लिए एनडीए सरकार की व्यग्रता उसकी अवसरवादी राजनीति की पोल खोल देने के लिए काफी है। साम्राज्यवादी ताकतों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उनकी सरकार इराक में भारतीय सेनाएं भेजने की हद तक चली गई थी।

भाजपा अपने साम्प्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है; इस मामले में वह अधिकाधिक आक्रमक होती चली जा रही है; यह सब वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर कर रही है; दूसरी ओर वह बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, दरिद्रता और जन विरोधी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के खिलाफ लोगों में बढ़ते असंतोष का बेजा फायदा उठाना चाहती है। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। एक बात स्पष्ट है, लोक सभा में प्रमुख विपक्षी दल होने पर भी वह सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुए लोगों के दुःखों–तकलीफों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ मोर्चा लेने की बजाए अपने विभाजक हिन्दुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है।

सेतुसमुद्रम परियोजना पर उसने जी जान से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया और अदालती मामले में सरकार की गलती से बेजा फायदा उठाने की कोशिशें की, उससे उसके घिनौने खेल की पोल खुल जाती है। चुनाव करीब आने के कारण भाजपा और अधिक जोरशोर से अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

लोगों में बढ़ता असंतोष

कोलकाता में मई 2007 में आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में पेश महासचिव रिपोर्ट में हमने उल्लेख किया था कि यूपीए सरकार अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों को ही लागू कर रही है और इसके परिणामस्वरूप "लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों और दिल्ली एवं मुम्बई के स्थानीय निकायों के चुनावों में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। इन घटनाओं का सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि लोग कांग्रेस पार्टी से निराश होते चले जा रहे हैं और इस स्थिति का लाभ भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों जैसी प्रतिगामी ताकतों को मिला है। उत्तर प्रदेश भले ही इसका अपवाद रहा हो। श्रमिक आंदोलन के लिए निश्चित रूप से यह घोर चिंता का विषय है।"

भारत–अमरीका परमाणु सौदे के विवाद के बीच बढ़ रही राजनीतिक अनिश्चितता के कारण होने जा रहे राजनीतिक संघर्ष में श्रमिक वर्ग को अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा। हमारा पूरा संघर्ष नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ है और हमें साम्राज्यवाद के विरोध में और अधिक मुखर होना होगा और अपनी लड़ाई को साम्राज्यवाद विरोध पर केन्द्रित करना होगा। हमें अपनी कमजोरियां दूर करनी होंगी और अपने संघर्ष को वाम दलों और प्रगतिशील ताकतों की ओर से देश भर में चलाए जा रहे साम्राज्यवाद विरोधी अभियान के साथ जोड़ना होगा। श्रमिक वर्ग को वाम एवं प्रगतिशील ताकतों के साथ मिल कर सत्ताधारी वर्ग के मिथ्या एवं भ्रामक प्रचार अभियान का मुंह तोड़ उत्तर देना होगा; सत्ताधारी वर्ग आगामी राजनीतिक संघर्ष के दौरान साम्राज्यवादी एजेंसियों की शह पर और अधिक आक्रमक रुख अपना सकता है। हमें भाजपा की साम्राज्यवाद परस्त और भूमण्डलीयकरण समर्थक नीतियों तथा उसके साम्प्रदायिक एजेंडे को बेनकाब

करना होगा क्योंकि वह दोबारा सत्ता में आने के लिए लोगों में पनप रहे रोष, आक्रोश और असंतोष का बेजा फायदा उठाने की कोशिशें कर रहा है।

इसके साथ ही हमें महंगाई, बेरोजगारी की बद से बदतर होती जा रही स्थिति, बढ़ती गरीबी, उद्योगों तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में कामगारों के अधिकारों एवं आजीविका पर बढ़ती हमलों के खिलाफ तृणमूल स्तर पर व्यापक जन लामबंदी करनी होगी और संघर्षों का निर्माण करना होगा। यूपीए सरकार अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में व्यक्त की गई जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रही है; उसे बेनकाब करने के लिए हमें अभियान चलाना होगा। यूपीए सरकार जन वितरण प्रणाली को मजबूत नहीं बना सकी; वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सर्व समावेशी कानून नहीं बना सकी, इन सब को बेनकाब करना होगा। हमें लोगों को यह बात समझा देनी होगी कि जन साधारण की आजीविका पर हो रहे इन हमलों का सीधा ताल्लुक भूमण्डलीयकरण की नीतियों के साथ है; ये नीतियां अमरीका तथा पश्चिम युरोप की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के इशारों पर लागू की जा रही हैं।

वाम पक्षी दलों ने परमाणु सौदे पर दृढ़ रुख अपनाया था। इसलिए अमरीका समर्थक ताकतों की ओर से वाम दलों के खिलाफ झूठा निंदा अभियान चलाना स्वाभाविक है। वे इस हालत में चुप नहीं बैठ सकते थे। श्रमिक वर्ग को इस कुत्सा प्रचार अभियान को विफल बनाना होगा। यह झूठा प्रचार अभियान बुर्जुआ मीडिया, सत्ताधारी दल और उनके गुर्गों द्वारा चलाया जा रहा है; ये सभी ताकतें देश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था को दक्षिणपंथी मोड़ देने पर तुली हुई हैं। इसके साथ ही साथ भाजपा तथा दूसरी साम्प्रदायिक ताकतें देश में साम्प्रदायिकता फेलाने के लिए खतरनाक अभियान चला रही हैं। यह एक सांगठनिक, आंदोलनात्मक और विचारधारक कार्य है और इसे पूरा करना सीआइटीयू का पहला फर्ज है।

बढ़ती महंगाई

महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका जबरदस्त दुष्प्रभाव शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और मजदूरों पर पड़ रहा है। गांवों में रहने वाले गरीब उत्पादकों के लिए भी विकट स्थिति बनी हुई है। जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं, अनाजों और दालों इत्यादि के मूल्य आकाश की ऊंचाईयों को छू रहे हैं। किन्तु जो लोग गांवों में इनका उत्पादन करते हैं, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। उनके लिए अपने जीवन स्थितियों को बनाए रखना मुशकिल हो गया है। दूसरी ओर एफसीआइ बुनियादी खाद्य वस्तुओं की खरीद के अपने लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रही है। खाद्यान्नों की खरीद करने के मामले में निजी क्षेत्र जिनमें विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं, का बोलबाला है। इस पर भी सरकार विशेष तौर पर उसके कृषि मंत्री जनाब शरद पवार यही दर्शाते चले जा रहे हैं कि किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य मिल रहे हैं।

एफसीआइ की पिछले एक साल की खरीद नगण्य रही है; कम से कम अनाज की खरीद सम्बन्धी आंकड़े यही दर्शाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में रबी फसलों के कुल उत्पादन में एफसीआइ की खरीद न के बराबर रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि इन राज्यों के किसानों को उनकी उपज के लिए वाजब दाम मिल रहे हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है; वह भी उस समय जब खरीद करने वाली एजेंसियां निजी क्षेत्र की हों। तृण मूल स्तर की स्थिति उसके ठीक विपरीत है जिसका बखान सरकार करती है।

कार्पोरेट खरीद एजेंसियों की ओर काम पर रखे गए दलाल लाभ पर लाभ कमा रहे हैं और निचले स्तर पर उपज बेचने वाले किसान उनके कठोर व्यवहार से त्रस्त हो रहे हैं। वास्तव में, यह पूरी व्यवस्था ही उत्पीड़नकारी है और यह व्यवस्था जमाखोरों और दलालों के लिए लाभकारी है। सरकार उदारता के साथ अनाज का आयात कर रही है; वह लाखों टन अनाज का आयात उससे कहीं अधिक दाम चुका कर रही है जो हमारे गरीब किसानों को उनकी उपज के लिए दिए जाते हैं। वह जानबूझ कर इस तरह की हालत पैदा कर रही है कि कृषि का धंधा किसानों के लिए लाभदायक न रहे।

पिछले छः महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखा जाए तो पता चलेगा कि तेजी से बढ़ती चली जा रही महंगाई उसमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित नहीं हो रही। सीआइटीयू को इस धोखेबाजी वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के खिलाफ संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के लिए पहल करनी होगी। उदाहरण के लिए सितम्बर 2006 से जून 2007 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) में केवल पांच अंकों की बढ़ोतरी हुई है; वह 125 से बढ़ कर 130 हो गया है। वास्तव में, दालों, अनाजों, सब्जियों तथा दवाओं इत्यादि सभी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों इस अवधि में 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हो चुकी है। यह एक अनुपात है। सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से (2001=100) श्रृंखला का विरोध किया था, पर सरकार ने उसकी परवाह न करके और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की अनदेखी करके नयी श्रृंखला लागू कर दी थी।

प्रधान मंत्री ने एक वर्ष पहले श्रमिक संगठनों को आश्वासन दिया था कि मूल्य सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किया जाएग। सरकार ने इस तरह की समिति का गठन किया पर उसमें श्रमिक संघों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके इरादे साफ हैं। सरकार आंकड़ों की जादूगरी करके सूचकांक की संख्याओं को कम दिखाने की कोशिश भले ही करे पर मजदूरों का एक बहुत बड़ी वर्ग उसकी इसी जादूगरी के कारण महंगाई भत्ते से वंचित हो रहा है।